vinetur

हेस्से जर्मनी में स्पार्कलिंग वाइन, चीनी और तंबाकू पर प्रस्तावित कर बढ़ोतरी का विरोध करेगा

यह विरोध बर्लिन की उस कोशिश को जटिल बना सकता है, जिसमें वह €2.5 billion की ईंधन कर कटौती को उपभोक्ता करों में बढ़ोतरी के साथ जोड़ना चाहता है।

गुरुवार, 24 सितंबर 2026



जर्मनी के बुंडेसराट में संघीय सरकार की प्रस्तावित कर बढ़ोतरी के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ रहा है, और हेस्से ने गुरुवार को कहा कि वह उन ऊंचे करों का विरोध करेगा जिनका असर स्पार्कलिंग वाइन, चीनी और तंबाकू सहित उत्पादों पर पड़ेगा।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब जर्मनी का रूढ़िवादी-सामाजिक लोकतांत्रिक गठबंधन एक क्षेत्र में उपभोक्ताओं को राहत और दूसरे में नया राजस्व जुटाने की कोशिश कर रहा है। तात्कालिक राजनीतिक तनाव समय और संदेश को लेकर है : राज्य सरकारों से ईंधन कर में कटौती के लिए मदद मांगी जा रही है, जिसका उद्देश्य चालकों पर दबाव कम करना है, जबकि बर्लिन कुछ चयनित उपभोक्ता वस्तुओं पर ऊंचे कर भी तैयार कर रहा है।

“वर्तमान स्थिति में, किसी भी तरह की कर बढ़ोतरी को खारिज किया जाना चाहिए, चाहे वह स्पार्कलिंग वाइन, चीनी या

तंबाकू पर हो," हेस्से के संघीय मामलों के मंत्री और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य मानफ्रेड पेंट्ज़ ने बर्लिन में कहा, Reuters के अनुसार। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं की लागत कम नहीं कर सकती और फिर सुपरमार्केट में उनसे पैसा वापस नहीं ले सकती।

पेंट्ज़ ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं पर बोझ डालने वाले संबंधित प्रस्ताव सामने लाए जाते हैं, तो हेस्से बुंडेसराट में इस रुख को स्पष्ट करेगा। उनकी टिप्पणियां गठबंधन की कर योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों में व्यापक बेचैनी की ओर इशारा करती हैं, हालांकि सभी उपायों को एक जैसी विधायी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता।

पृष्ठभूमि का एक हिस्सा ऊर्जा कर में एक अस्थायी कटौती है, जिसका उद्देश्य ईंधन की कीमतें कम करना है। जर्मनी के राज्यों को शुक्रवार को इस उपाय को मंजूरी देनी है और लागत का आधा हिस्सा वहन करना है, जो तीन महीने में €2.5 billion बैठता है। साथ ही, संघीय सरकार वैधानिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में उपायों की वित्त व्यवस्था करने के लिए तंबाकू और चीनी करों में बढ़ोतरी की योजना बना रही है।

स्पार्कलिंग वाइन पर बहस ने खास ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें वाइन-उत्पादक राज्यों की भूमिका है और यह उपाय संसद में अपेक्षाकृत संकरी राह से गुजरता है। Reuters के अनुसार, बुंडेसराट शुक्रवार को स्पार्कलिंग वाइन कर में प्रस्तावित बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता क्योंकि उपाय को जर्मन कानून के तहत आपत्ति विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह सदन इसे टाल सकता है, लेकिन अकेले अंतिम रूप से रोक नहीं लगा सकता।

हेस्से बाडेन-वुर्टेमबर्ग, बवेरिया और राइनलैंड-पैलेटिनेट सहित अन्य वाइन राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है, जो इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं और अपने वाइन उत्पादकों को ध्यान में रखकर साथ काम कर रहे हैं। इन राज्यों में जर्मनी के वाइन उद्योग का बड़ा हिस्सा स्थित है, और क्षेत्रीय सरकारों की इस बात में सीधी राजनीतिक रुचि है कि उत्पादकों को उन ऊंची लागतों से बचाया जाए जो बिक्री को कमजोर कर सकती हैं या पहले से ही तंग मार्जिन पर और दबाव डाल सकती हैं।

इसका असर राजनीति से बाहर भी पड़ता है। स्पार्कलिंग वाइन पर कर बढ़ोतरी खुदरा कीमतों, प्रचार बजट और उत्पादक मार्जिन तक पहुंच सकती है, खासकर उन वाइनरी और पेय कंपनियों के लिए जो कीमत के प्रति संवेदनशील खंडों में बिक्री करती हैं। अगर यह उपाय आगे बढ़ता है, तो यह जर्मन स्पार्कलिंग वाइन की कीमत को अन्य मादक पेयों और आयातित विकल्पों के मुकाबले प्रभावित कर सकता है। अगर बुंडेसराट योजना को केवल धीमा भी करता है, तब भी अनिश्चितता आने वाले बिक्री दौरों से पहले वाइन उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की योजना बनाने को मुश्किल बना सकती है।

उभरता हुआ विरोध यह भी दिखाता है कि जब कर नीति रोजमर्रा की खरीद पर असर डालती है, तो समर्थन कितना नाज़ुक हो सकता है। पेंट्ज़ का तर्क इस मुद्दे को केवल वाइन क्षेत्र तक सीमित नहीं रखता, बल्कि सीधे घरेलू बजट से जोड़ता है। उनकी आलोचना ने स्पार्कलिंग वाइन, चीनी और तंबाकू को एक ही राजनीतिक ढांचे में रखा : ऐसे उत्पाद जिन पर तब अधिक कर लगाया जा सकता है, जब सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही हो कि वह कहीं और लागत का बोझ कम कर रही है।

संघीय सरकार के लिए तंबाकू और चीनी पर ऊंचे करों का तर्क स्वास्थ्य नीति के वित्तपोषण से जुड़ा है। बर्लिन सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में उपायों के लिए अतिरिक्त धन चाहता है, और लक्षित उत्पाद-कर राजस्व जुटाने का राजनीतिक रूप से परिचित तरीका देते हैं। लेकिन राज्य नेता संकेत दे रहे हैं कि जहां संघीय सरकार के पास कानूनी बढ़त है, वहां भी उसे आर्थिक और राजनीतिक परिणामों पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

कानून के प्रकार के आधार पर बुंडेसटाग और बुंडेसराट अक्सर शक्ति को अलग-अलग तरह से बांटते हैं। इस मामले में यही अंतर केंद्रीय है। क्योंकि स्पार्कलिंग वाइन कर का उपाय उस श्रेणी में आता है जिसमें केवल आपत्ति की अनुमति होती

है, इसलिए राज्यों की पकड़ सीमित है। फिर भी, देरी मायने रखती है। इससे और बहस करवाई जा सकती है, सरकार के लिए राजनीतिक लागत बढ़ सकती है और प्रभावित उद्योगों को बढ़ोतरी के खिलाफ लॉबिंग करने के लिए ज्यादा समय मिल सकता है।

यह टकराव बर्लिन द्वारा अपनाई जा रही व्यापक राजकोषीय रणनीति में तनाव को भी उजागर करता है। एक ओर, गठबंधन ईंधन पर कर कटौती का समर्थन कर रहा है और राज्यों से लागत का हिस्सा उठाने को कह रहा है। दूसरी ओर, वह ऐसे उत्पादों पर ऊंचे करों के जरिए नया राजस्व ढूंढ रहा है, जिन्हें निशाना बनाना आसान है और स्वास्थ्य के आधार पर राजनीतिक रूप से बचाव योग्य माना जाता है। पेंट्ज़ जैसे राज्य अधिकारी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये दो संदेश मतदाताओं को एक साथ बेचे जा सकते हैं।

Reuters ने बताया कि हेस्से वाइन राज्यों के बीच विरोध को संगठित करने में अगुवाई कर रहा है। यह समन्वय दिखाता है कि प्रतिरोध किसी एक क्षेत्रीय शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे देश के वाइन और स्पार्कलिंग वाइन उत्पादन में प्रत्यक्ष हित रखने वाले राज्यों के एक सामूहिक प्रयास में बदला जा रहा है।

शुक्रवार की बुंडेसराट बैठक यह परखेगी कि यह प्रतिरोध कितनी दूर तक जा सकता है। ईंधन कर कटौती के मामले में, राज्यों के समक्ष ऐसा उपाय तय करने का प्रस्ताव है जो €2.5 billion के बोझ को तीन महीने में बांटेगा। स्पार्कलिंग वाइन कर के मामले में, विरोधियों के पास योजना को सीधे रोकने के लिए न तो पर्याप्त वोट हो सकते हैं और न ही कानूनी औजार, लेकिन वे फिर भी सदन का उपयोग उस नीति के खिलाफ अपना पक्ष रखने के लिए कर सकते हैं, जिसे उनके अनुसार उपभोक्ताओं की लागत बढ़ेगी और जर्मनी के पेय उद्योग के एक संवेदनशील हिस्से पर चोट पड़ेगी।